

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 174/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

महेन्द्र यादव वगैरह ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

बिरेन्द्र यादव वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

17-01-25

प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 21.12.2024 की तिथि से निषेधाज्ञा प्रभावी कर उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया-

विवादित भूमि का विवरण

मौजा- सबलपुर, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह
खाता नं0- 169, प्लॉट नं0- 38, रकबा- 3.33 डी0
चौहद्दी : - 30- जुमन मियां,
द0- कोली महतो,
पू0- झरी गोप,
प0- राजधनवार रोड़

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा की गई।

उभय पक्ष अघोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ किस्म की है तथा उनके पूर्वज को हुकुमनामा से हासिल है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, एक Online पंजी-II की छायाप्रति, एक रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं।

वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें खरीदगी हासिल है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक पंचनामा की छायाप्रति, एक लगान रसीद की छायाप्रति, एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति संलग्न करते हैं। साथ ही निर्मित मकान संबंधी दो रंगीन फोटोग्राफ भी मूल रूप से संलग्न करते हैं।

अंचल अधिकारी सरिया का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त है। उक्त

प्रतिवेदन के अनुसार वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा किस्म जमीन जंगल दर्ज है।

उपरोक्त दस्तावेजों के अध्ययन, अंचल अधिकारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष सादा हुकुमनामा के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना- अपना दावा करते हैं।

चूँकि मामला गैरमजरूआ जमीन का है तथा किस्म जमीन जंगल है अतः उक्त जमाबन्दी की वैधता पर निर्णय लेना अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसी जमाबंदियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतः अंचल अधिकारी सरिया को निदेशित किया जाता है कि उक्त जमाबंदी की सम्यक् समीक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध न्याय निर्णय Civil writ 202/95 dated 12/12/1996 T.N. Godavarman Thirumal Vs Union of India & Ors.

“the term ‘Forest land’ occurring in section 2 will not only include ‘forest’ as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as Forest in the Government record irrespective of ownership” तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 8/78/1996-FC(pt) dated 10th March 2015 के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे तथा तदुपरांत संतुष्ट होकर झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(h) के तहत विधिसम्मत कार्यवाई आरंभ करेंगे। उक्त संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स. भू. (दिशा निर्देश) 95/2016-2074/रा0 दिनांक 13/5/2016 तथा अन्य प्रासंगिक पत्रों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में इस वाद के किसी भी पक्ष के हित में कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद की कार्यवाई बिना किसी अंतिम आदेश के समाप्त की जाती है। प्रभावित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी सरिया तथा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

17-1-25
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

17-1-25
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया